nt>
Title: Need to review the export policy of copper to maintain balance in the International market.

श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का अत्यंत ही महत्वपूर्ण उद्यम हिंदुस्तान कोपर लिमिटेड है। भारत सरकार की कच्चे माल कौपर की जो आयात नीति है उसमें जो शुल्क का निर्धारण पिछले साल में किया गया है, उसमें विशेष छूट दी गयी है, जिसके कारण देश के कौपर के प्रोजेक्टस करोड़ों रुपये के घाटे में जा चुके हैं। बालाघाट जिले का मलाछखंड कौपर प्रोजेक्ट करोड़ों रुपये के घाटे में जा चुका है और उसका घाटा दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है। यदि भारत सरकार ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया दो एक दिन ऐसा आएगा कि आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में जो उपक्रम लगे हैं वे बंद होने के कगार पर आ जाएंगे और इनमें काम करने वाले लाखों श्रमिकों के परिवारों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। यह जो कौपर की आयात नीति है इसके संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इसमें गंभीरता से चिंतन करे और कम से कम इस तरह का डिसीजन रखे कि भारत में पैदा होने वाला कौपर दुनिया के बाजार को फेस कर सके। भारत में पैदा होने वाले कौपर की कोस्ट ज्यादा रहने का कारण हमारी पुरानी प्रौद्योगिकी है। यह कौपर की आयात नीति और मार्किट को बैलेंस करने का महत्वपूर्ण विषय है। आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस्पात और खान मंत्री, वित्त मंत्री इसकी चिंता करें और बैठकर इसके ऊपर निर्णय लें जिससे कि हिंदुस्तान का कौपर दुनिया के बाजार में अपना स्थान बन सके, नहीं तो पूरा कौपर उद्योग रसातल में चला जाएगा।